भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2103** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

जहाज निर्माण वित्त में जोखिम बीमा कवर

†2103. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई प्रमुख जहाज निर्माण देशों में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जहाज निर्माण वित्त में वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य समर्थित जोखिम बीमा कवर प्रदान किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ऐसे जोखिम शमन तंत्रों के अभाव ने जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए ऋण देने की बैंकों की इच्छा को प्रभावित किया है या इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरें बढ़ी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए ऋणदाताओं की सुरक्षा और पूंजी की लागत को कम करने के लिए देश में इसी प्रकार की जोखिम बीमा योजना शुरू करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के कब तक लागू होने की उम्मीद है;

(ङ) भारतीय शिपयार्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता और जहाज निर्माण वित्त की समग्र लागत पर ऐसे तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है; और

(च) देश में जहाज निर्माण वित्त को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): जी हां, कई प्रमुख पोत निर्माण राष्ट्रों में, अग्रणी राज्य समर्थित वित्तीय संस्थान पोत निर्माण क्षेत्र हेतु जोखिम इंश्योरेंस प्रदान करते है। भारत में, अभी तक ऐसी योजना अनुमोदित नहीं की गई है।

****